वोडाफोन-आइडिया को सहारा

2040 -41 तक बकाया लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम शुल्क में दी मोहलत | **49** प्रतिशत शेयरधारक है सरकार वर्तमान में कंपनी की

नई दिल्ली, 31 दिसंबर. केंद्र सरकार ने वोडाफोन आइडिया को बड़ा आर्थिक राहत पैकेज देते हुए कंपनी के 87,695 करोड़ रुपये के बकाया लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के भुगतान के लिए 2040-41 तक की मोहलत दी है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस बकाया पर कंपनी को कोई ब्याज या जुर्माना नहीं देना होगा। कंपनी को यह राशि 2031-32 से 2040-41 तक किस्तों में चुकानी होगी। वोडाफोन आइडिया ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद सरकार से राहत की मांग की थी। यह निर्णय

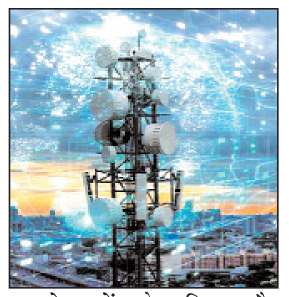

उपभोक्ताओं के हित और दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की दृष्टि से लिया गया है। सरकार वर्तमान में कंपनी की 49 प्रतिशत शेयरधारक है और बकाया राशि की किस्तों में अदायगी से उसके नकदी प्रवाह में स्थिरता बनी रहेगी। मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग को निर्देश दिया है कि वह दिसंबर 2025 तक की समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) आधारित बकाया राशि का पुन: आकलन करे। इससे एजीआर प्रणाली के तहत शुल्क निर्धारण और कटौती की पुष्टि की जाएगी। केंद्र सरकार ने वोडाफोन आइडिया को वित्तीय संकट से उबारने और दूरसंचार बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने कंपनी के 87,695 करोड़ रुपये के बकाया लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भुगतान 2040-41 तक करने की मोहलत दी है। इस राहत के तहत कंपनी को ब्याज या किसी प्रकार का जुर्माना नहीं देना होगा। कंपनी को यह राशि 2031-32 से 2040-41 तक किस्तों में चुकानी होगी।

> वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय एक बड़ी दूरसंचार कंपनी को दबाव से मुक्त करने का संतुलित उपाय है, जिससे पूरे क्षेत्र में निवेश और सेवा की गुणवत्ता बनी रहे। इस फैसले से वोडाफोन आइडिया अपने परिचालन और विस्तार योजनाओं में आसानी से निवेश कर सकेगी। साथ ही, कंपनी के ग्राहकों के लिए सेवाओं में स्थिरता बनी रहेगी और भारत के दूरसंचार क्षेत्र में व्यापक आर्थिक लाभ होगा।

एमएसई प्लेटफॉर्म पर चार कंपनियां सूचीबद्ध

मुंबई, 31 दिसंबर. शेयर बाजार बीएसई के मझौली और छोटी कंपनियों वाले एमएसई प्लेटफॉर्म पर चार नयी कंपनियां सूचीबद्ध हुई हैं। बीएसई ने बुधवार को जानकारी में बताया कि उसके एमएसई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाली नयी कंपनियां नैनटा टेक लिमिटेड, एडमैक सिस्टम्स लिमिटेड, बाई-काकाजी पॉलिमर्स लिमिटेड और अपोलो टेक्नो इंडस्ट्री लिमिटेड हैं। इसके साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर अब कंपनियों की संख्या 689 हो गयी है। चारों कंपनियों का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम 26 दिसंबर को बंद हुआ था. गुजरात के अहमदाबाद स्थित नैनटा टेक ऑडियो विजुअल (एवी) इंटीग्रेशन और एवी उत्पादों, सर्विस रोबोट तथा सेवाओं से संबंधित सॉफ्टवेयर के वितरण का कारोबार करती है।

नए साल में आरबीआई से राहत की उम्मीद

ब्याज दरों में और ज्यादा कटौती संभव

नई दिल्ली, 31 दिसंबर. नई दिल्ली- खुदरा महंगाई में कमी और मजबूत आर्थिक वृद्धि ने इस बात की उम्मीद बढ़ा दी है कि भारतीय रिजर्व बैंक नए साल 2026 में नीतिगत राहत दे सकता है. 2025 में केंद्रीय बैंक ने छह मौद्रिक नीति समीक्षाओं में से चार में अपनी प्रमुख दरों में कुल 1.25प्रतिशत की कटौती की. गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि यह कदम वृद्धि को समर्थन देने के लिए उठाया गया.

हालांकि, रुपये के प्रबंधन ने सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. 2025 में घरेलू मुद्रा लगातार कमजोर हुई और डॉलर के मुकाबले 85.64 रुपये पर बंद हुई. केंद्रीय बैंक ने बाजार में हस्तक्षेप से उतार-चढ़ाव कम किया, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार से 38 अरब डॉलर की बिक्री करनी पड़ी. विशेषज्ञों का मानना

है कि 2026 में याज दरों में और कटौती कर सकता है, लेकिन रुपये के उतार-चढ़ाव और मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर निगरानी बनी रहेगी. बैंकों को दरों में संभावित कटौती से शुद्ध ब्याज मार्जिन पर असर पड़ सकता है, लेकिन पर्याप्त नकदी और नियामकीय ढील से यह प्रभाव कुछ हद तक कम होगा.

> गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस साल छह मौद्रिक नीति समीक्षाओं में से चार में कुल 1.25 प्रतिशत कटौती की. फरवरी और जून में की गई कटौती विशेष रूप से वृद्धि को समर्थन देने और नीतिगत ढील प्रदान करने के उद्देश्य से थी. मल्होत्रा ने अपनी पहली वर्षगांठ पर मौजूदा आर्थिक स्थिति को भारत के लिए संतुलित दौर करार दिया. अमेरिका के टैरिफ, भू-राजनीतिक बदलाव और वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव के बावजूद वृद्धि दर आठ प्रतिशत से अधिक रही और महंगाई एक प्रतिशत से नीचे रही. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि आगे चलकर वृद्धि दर थोड़ी नरम पड़ सकती है और खुदरा महंगाई आरबीआई के चार प्रतिशत लक्ष्य के करीब लौट सकती है.

लव अग्रवाल होंगे नये डीजीएफटी

नई दिल्ली, 31 दिसंबर. भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी लव अग्रवाल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के नये महानिदेशक होंगे।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार 1996 बैच के आंध्र प्रदेश काडर के आईएएस श्री अग्रवाल इस पद पर श्री अजय भादू का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल अभी तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। वह इससे पहले अगस्त 2016 से अगस्त 2022 तक भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। केंद्र सरकार में अपनी नियुक्ति से पहले श्री अग्रवाल ने आंध्र प्रदेश सरकार के विभिन्न पदों पर कार्य किया था। लव अग्रवाल का जन्म 18 फरवरी 1972 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। सरकार ने वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत सुचिंद्र मिश्रा को सचिव पद पर प्रोन्नत कर इसी विभाग में अतिरिक्त सचिव के एक रिक्त पड़े पद का दायित्व दिया गया है जिसे अस्थायी रूप से उन्नत कर सचिव स्तर का कर दिया गया है।

सोने-चांदी के दाम धड़ाम, निवेशकों को लगा झटका

1500 रुपए नीचे आया सोना

15000 रुपए कम हुई चांदी

नई दिल्ली, 31 दिसंबर. नए साल से ठीक पहले सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों ने निवेशकों और ग्राहकों दोनों को चौंका दिया है. लंबे समय से ऊंचाई पर बने हुए गोल्ड और सिल्वर के भाव में आज जोरदार गिरावट दर्ज की गई.

एक ही दिन में सोना 1500 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया, जबकि चांदी के दामों में 15 हजार रुपये तक की टूट देखने को मिली है. सर्राफा बाजार में बुधवार, 31 दिसंबर को सोने-चांदी के भाव में

भारी गिरावट दर्ज की गई. एमसीएक्स के बाद अब बुलियन मार्केट में भी कीमती धातुओं के दाम तेजी से फिसल गए. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज सोना 1500 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया, जबकि चांदी के भाव में करीब 15 हजार रुपये प्रति किलो तक की गिरावट देखने को मिली. आज बिना जीएसटी चांदी 229433 रुपये प्रति किलो पर आ गई, जबकि जीएसटी समेत इसकी कीमत 236315 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई. वहीं, 24 कैरेट सोने का रेट बिना जीएसटी 134599 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा और टैक्स जोड़ने के बाद यह 137091 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

> कैरेट के हिसाब से देखें तो 22 कैरेट सोना 1374 रुपये टूटकर 121919 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जबकि जीएसटी समेत इसकी कीमत 125576 रुपये है. 18 कैरेट गोल्ड भी 1374 रुपये की गिरावट के साथ 99824 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं, 14 कैरेट सोने के दाम 877 रुपये गिरकर 77863 रुपये पर आ गए हैं. गौरतलब है कि 29 दिसंबर को सोना 138181 रुपये के ऑलटाइम हाई पर था, जहां से अब यह 5000 रुपये से ज्यादा टूट चुका है.

आईसीआईसीआई बैंक को 16 करोड़ रुपये का नोटिस

मुंबई, 31 दिसंबर. निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग से 16 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के लिए नोटिस जारी किया गया है. बैंक ने बुधवार को शेयर बाजार को बताया कि उसे 30 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के राजस्व उपायुक्त से 16,03,30,178 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है. इसमें 8,67,57,468 रुपये के कर, 6,48,96,963 रुपये के ब्याज और 86,75,747 रुपये के जुर्माने की मांग की गयी है. यह मामला ग्राहकों से बैंक खाते में न्यूनतम जमा राशि न रखने के लिए वसूले गये शुल्क पर जीएसटी की राशि सरकार को जमा न कराने से संबंधित है.

इंडिगो को 458 करोड़ का नोटिस

जीएसटी का बड़ा झटका, अब तक दिए तीन नोटिस

नई दिल्ली, 31 दिसंबर. निजी विमान सेवा कंपनी इंडिगो को वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने 458.26 करोड़ रुपये से अधिक के लिए दो अलग-अलग नोटिस जारी किये हैं. दिसंबर के पहले सप्ताह में बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करने के बाद कंपनी को जीएसटी विभाग से अब तक तीन नोटिस मिल चुके हैं.

एयरलाइंस ने मंगलवार को शेयर बाजार को बताया कि उसे दक्षिणी दिल्ली कमीशनरेट में केंद्रीय जीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त से 29 दिसंबर को यह नोटिस प्राप्त हुआ है. इसमें 4,58,26,16,980 रुपये का जीएसटी, ब्याज और जुर्माना भरने के लिए कहा गया है. यह मांग वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए है. जीएसटी विभाग ने इस नोटिस में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त मुआवजे पर जीएसटी के साथ ब्याज और जुर्माने की मांग की है. साथ ही कंपनी द्वारा लिये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी अवैध बताया गया है.

एयरलाइंस ने पुख्ता विश्वास जताया है कि जीएसटी विभाग द्वारा जारी आदेश त्रुटिपूर्ण और कानून के खिलाफ है. उसने कहा है कि वह इसे चुनौती देगी और समुचित वैधानिक उपाय करेगी. कंपनी ने बताया है कि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इसी तरह के एक नोटिस के खिलाफ उसने अपील की है. दूसरा नोटिस लखनऊ के संयुक्त आयुक्त कार्यालय ने भेजा है. इसमें 14,59,527 रुपये जमा करने का आदेश दिया गया है. नोटिस 29 दिसंबर को मिला था. इसमें वित्त वर्ष 2021 एयरलाइन द्वारा लिए गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवैध करार देते हुए यह राशि, उस पर ब्याज और जुर्माने की मांग की गयी है.

> कंपनी ने कहा है कि वह इस आदेश के खिलाफ भी अपील करेगी. इससे पहले, दक्षिणी दिल्ली कमीशनरेट की तरफ से ही कंपनी को 11 दिसंबर को 58.75 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का नोटिस दिया गया था. नोटिस में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एयरलाइंस से 58 करोड़ 74 लाख 99 हजार 439 रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा गया था.

विदेशी सिम पर ट्राई की बड़ी पहल

नई दिल्ली, 31 दिसंबर. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने निर्यात के उद्देश्य से बनाये गये एम2एम/आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्डों की बिक्री के लिए नियामक संरचना पर अपनी सिफारिशें मंगलवार को जारी कर दीं.

ट्राई ने इस साल 04 जुलाई को निर्यात के लिए बनाये गये एम2एम/आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम

कार्डों की बिक्री के लिए नियामक संरचना विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया था. इस पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और ऑनलाइन माध्यम से खुली बैठक में प्राप्त सुझावों के बाद ट्राई ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप प्रदान किया है. संचार मंत्रालय ने बताया कि एम2एम/आईओटी उपकरणों (जैसे स्मार्ट मीटर, कनेक्टेड कार, औद्योगिक सेंसर) के भारतीय निर्माताओं को प्राय: विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्ड को अंत:स्थापित करने की आवश्यकता होती है ताकि उपकरण गंतव्य देश में निर्बाध रूप से सेवा प्रदान कर सकें. वर्तमान में निर्यात के लिए बनाये गये एम2एम/आईओटी उपकरणों में विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्डों की बिक्री के लिए देश में कोई नियामक संरचना मौजूद नहीं है.

अबक्कस म्यूचुअल फंड ने पहले एनएफओ से जुटाये 2,468 करोड़ रुपये

मुंबई, 31 दिसंबर. अबक्कस म्यूचुअल फंड ने अपने फ्लेक्सी कैप फंड के पहले न्यू फंड ऑफर के जरिये 2,468 करोड़ रुपये की राशि जुटायी है. कंपनी ने बुधवार को बताया कि 08 से 22 दिसंबर 2025 तक खुले रहे अबक्कस फ्लेक्सी कैप फंड के एनएफओ के दौरान कुल 2,468 करोड़ रुपये का निवेश आया है. एनएफओ में देश के लगभग दो हजार शहरों के लोगों ने निवेश किया है. एनएफओ अवधि के दौरान 36,688 खुदरा निवेशकों और 1,060 संस्थागत निवेशकों ने फंड में भागीदारी की.

शेयर बाजारों में लौटी तेजी सेंसेक्स 546 अंक मजबूत

मुंबई, 31 दिसंबर. बैंकिंग, ऑटो और अन्य सेक्टरों में लिवाली से घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को तेजी रही और बीएसई का सेंसेक्स 545.52 अंक (0.64 प्रतिशत) चढ़कर 85,220.60 अंक पर पहुंच गया.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 190.75 अंक यानी 0.74 प्रतिशत मजबूत हुआ और साल के अंतिम कारोबारी दिवस पर 26,129.60 अंक पर बंद हुआ. मझौली और छोटी कंपनियों में भी लिवाली हावी रही. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 1.14 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 1.11 प्रतिशत की बढ़त में रहा. आईटी को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरों में लिवाली रही. तेल एवं गैस, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद, रसायन, बैंकिंग, ऑटो, धातु और स्वास्थ्य सेक्टरों के सूचकांक एक प्रतिशत से ऊपर चढ़े. सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा स्टील का शेयर करीब ढाई प्रतिशत और कोटक महिंद्रा बैंक का लगभग दो प्रतिशत टूट गया.

समाचार विशेष

प्रथम पृष्ठ का शेष

दिग्विजय की टिप्पणी से कांग्रेस में बहस तेज

अपने रुख को स्पष्ट करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं संगठन की सराहना करता हूं, लेकिन आरएसएस और मोदी जी की विचारधारा का सदैव मुखर विरोधी रहा हूं. मैंने संगठन की प्रशंसा की है, न कि उनकी विचारधारा की. सिंह के इस बयान पर कांग्रेस के भीतर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई. पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि नाथूराम गोडसे से जुड़े संगठन से गांधीवादी विचारधारा पर आधारित कांग्रेस क्या सीख सकती है. कई अन्य नेताओं ने भी सिंह की टिप्पणी से दूरी बनाते हुए कांग्रेस और आरएसएस के बीच वैचारिक अंतर को रेखांकित किया. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिग्विजय सिंह की टिप्पणी कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक कमजोरी और आंतरिक असंतोष की ओर इशारा करती है. दो बार मुख्यमंत्री रह चुके और 5 दशक से पार्टी से जुड़े सिंह को जमीनी स्तर पर संगठन की कमजोर पकड़ को लेकर चिंतित माना जा रहा है. उनका यह बयान वैचारिक समर्थन से अधिक संगठनात्मक सुधार की अपील के रूप में देखा जाना चाहिए, उनका तर्क है कि संगठनात्मक दक्षता और विकेंद्रीकृत नेतृत्व जैसे पहलुओं से कांग्रेस व्यावहारिक सबक ले सकती है. दिग्विजय सिंह के अनुसार संदेश साफ है- वैचारिक विरोध के बावजूद प्रतिद्वंद्वी की संगठनात्मक ताकत से सीख लेने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए.

दूषित पानी से मृतक की संख्या 12

डॉक्टरों ने उसे बाहरी दूध देने का बोला था जिसके चलते उसके दूध में पानी मिला कर दिया जाता था, क्या पता था कि यही पानी उसकी मौत का कारण बन जाएगा. अन्य मृतक के नाम जीवनलाल बरेडे, शंकर लाल और अशोक पवार हैं.

पीने के पानी की स्थिति को लेकर नगर निगम हरकत में आया लेकिन भागीरथपुरा में हालात फिलहाल सामान्य नहीं हैं. लोग साफ पानी, पारदर्शी जांच और जिम्मेदारों पर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन इलाके में पसरी खामोशी बता रही है कि भरोसा अभी भी डगमगाया हुआ है.

डीआरडीओ ने दागीं दो 'प्रलय' मिसाइलें

प्रलय देश में ही विकसित ठोस ईंधन आधारित अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें उच्च सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणाली का उपयोग किया है. यह मिसाइल विभिन्न लक्ष्यों के विरुद्ध अनेक प्रकार के मुखास्त्र ले जाने में सक्षम है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक के बाद एक दो मिसाइलों के सफल प्रक्षेपण पर डीआरडीओ, भारतीय वायु सेना, भारतीय सेना, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और उद्योग को बधाई दी. उन्होंने कहा कि प्रलय मिसाइल के सैल्वो प्रक्षेपण की सफलता ने मिसाइल की विश्वसनीयता स्थापित की है.

उत्तर भारतीयों का 'पश्चिम-नागपुर' पैटर्न

सियासी दलों की बड़ी चिंता

नागपुर. नागपुर मनपा चुनाव की सरगर्मी अब अपने चरम पर है. प्रमुख राजनीतिक दल जहां जाति के जुगाड़ में लगे हैं वहीं सिटी का उत्तर भारतीय समाज भी पूरे हौसले के साथ सभी प्रमुख दलों के फैसलों पर नजर गड़ाए हुए है.

उत्तर भारतीय समाज ने दो टूक चेतावनी दी है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह पश्चिम नागपुर में समाज ने खेला किया था, उसी पैटर्न को वह पूरे शहर में लागू करने जा रहा है. जाहिर है कि राजनीतिक दलों के निर्णायक नेतागण भी इस जोखिम

को समझ रहे हैं और वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कुछ भी गलत संदेश जाए.

विस चुनावों में दिखा था असर- वैसे तो पश्चिम नागपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 1990 के दशक से ही हिन्दी भाषियों और विशेष रूप से उत्तर भारतीयों का दबदबा रहा है.

एक समय था जब पश्चिम नागपुर की सीट पर कांग्रेस के बड़े नेता गेव आवारी को पराजित करने के लिए दिलीप चौधरी को मैदान में उतारा गया था. बाद में यह प्रयोग मनपा चुनाव में 1992 में देखने को मिला जब स्थायी समिति के अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस प्रत्याशी नाना मोहोड़ को हराने के लिए उत्तर भारतीय पहलवान जंग बहादुर सिंह अखाड़े में थे. उन्हें उतने ही वोट मिले थे जितने निर्दलीय रघुनाथ मालीकर को पार्षद के रूप में पारी शुरू करने के लिए पर्याप्त थे.

> **समाज का अपना वोट बैंक**
>
> समाज ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले गिट्टीखदान चौक पर हुई एक सभा में नारा बुलंद किया था. जो समाज का, समाज उसकाउ इस नारे का असर यह हुआ कि अब उत्तर भारतीय समाज का अपना एक वोट बैंक हो गया है. विधानसभा चुनाव में उत्तर भारतीय झटके का असर सबसे ज्यादा बीजेपी को देखने को मिला. शहर अध्यक्ष के रूप में दयाशंकर तिवारी की नियुक्ति को भी इसका असर बताया जा रहा है. सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस ने भी अपनी संभावित प्रत्याशियों की सूची में हिन्दी भाषियों के नाम रखे हुए हैं.

अहिंदा कन्वेंशन कौन करा रहा है?

बेंगलुरु. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आसानी से हथियार डालने वाले नहीं हैं. जनवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से उनकी मुलाकात होने वाली है. बताया जा रहा है कि राहुल गांधी उनसे मिलेंगे और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से भी मिलेंगे.

यानी कर्नाटक में चल रहे सत्ता संघर्ष का पटाक्षेप करने के लिए बैठक होगी. गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा चल रही है कि सिद्धारमैया जिस दिन सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का देवराज अर्स का रिकॉर्ड तोड़ देंगे उस दिन के बाद उनको मुख्यमंत्री पद से हटने में समस्या नहीं है. वे जनवरी के पहले हफ्ते में यह रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं.

लेकिन ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने के रिकॉर्ड वाली बात शिवकुमार के लोग ज्यादा फैला रहे हैं. सिद्धारमैया और उनके समर्थक ऐसा नहीं मान रहे हैं. वे मुख्यमंत्री पद छोड़ने के पक्ष में नहीं हैं. पिछले दिनों कर्नाटक में एक अहिंदा कन्वेंशन हुआ. सबको पता है कि अहिंदा समीकरण सिद्धारमैया का साधा हुआ है. जनता दल में रहते हुए उन्होंने इसकी राजनीति की थी और इसी समीकरण के लिए एचडी देवगौड़ा ने उनको अपने साथ रखा था.

विशेष | राज्यसभा की कितनी सीटों पर बदलेगा समीकरण?

देश की राजनीति में होंगे बड़े बदलाव

नई दिल्ली. नए साल में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे. सत्ता की चाबी यहां से वहां होने की उम्मीद है. पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे. राज्यसभा की 75 सीटों पर भी चुनाव होंगे. ये सीटें अप्रैल, जून और नवंबर में खाली होंगी. इससे एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सत्ता संतुलन में बदलाव आ सकता है.

आगामी चुनावों में बिहार और यूपी से राज्यसभा की 10-10 सीटें रिक्त होंगी. महाराष्ट्र, झारखंड,

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कई पूर्वोत्तर राज्यों में भी सीटें रिक्त होंगी. नया साल राज्यसभा चुनावों के राष्ट्रीय महत्व और भविष्य के विधायी एजेंडे पर उनके संभावित प्रभाव को दर्शाता है. जिन वरिष्ठ नेताओं का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है, उनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, दिग्विजय सिंह, शरद पवार और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन शामिल हैं. इनका राजनीतिक भविष्य अनिश्चित है, यह देखना बाकी है कि वे संसद में लौटेंगे या नए चेहरे आएंगे.

इन राज्यों से राज्यसभा सीटें होंगी खाली- अप्रैल-जून के बीच और फिर नवंबर में राज्यसभा में महाराष्ट्र की 7 और बिहार की 5 सीटें रिक्त होंगी. झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में भी रिक्तियां होंगी. उत्तर प्रदेश की 10 सीटें भी नवंबर तक खाली होनी हैं. इसी अवधि में मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा. इससे बदलाव का दायरा और भी बढ़ जाएगा.

> **महाराष्ट्र में क्या हालात?**
>
> महाराष्ट्र में अप्रैल में राज्यसभा की 7 सीटों पर चुनाव होंगे. शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जैसे प्रमुख नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा. महाराष्ट्र में पिछले साल के विधानसभा चुनावों के बाद राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है. शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी की संसद में वापसी की संभावना अनिश्चित है. सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को इन सीटों में से अधिकतर पर जीत मिलने की उम्मीद है. महाविकास अघाड़ी में सबसे अधिक विधायकों वाली कांग्रेस के सामने यह रणनीतिक विकल्प है कि वह अपने उम्मीदवार उतारे या सहयोगी दलों के उम्मीदवारों का समर्थन करे.

कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा क्रमश: जून और अप्रैल में राज्यसभा सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त होंगे. कर्नाटक की 4 सीटों पर चुनाव होंगे. कांग्रेस के तीन सीटें जीतने का अनुमान है.